MR. CHAIRMAN : Please excuse me.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : रूल सस्पेंड कर के जरा इनको मूव कर लेने दीजिये ।

श्री वेणीशंकर शर्मा (बांका) : मैं भी यह कहूंगा कि आचार्य कृपालानी जी को मूव कर लेने दिया जाय ।

SHRIMATI SHARADA MUKERJEE : I move that the Rule be suspended

SHRI S. KANDAPPAN : I support it.

सभापति महोदय : यह नहीं हो सकता । यह नियम का मामला है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वह इसे छोड़ दें हमारी उनके लिए कम रेस्पेक्ट नहीं है ।

We shall now take up the Half an-hour Discussion.

17.31 hrs.

HALF-AN HOUR DISCUSSION

Construction of Fertilizer Plants

श्री ओंकार लाल बोहरा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर मैं चर्चा उठाने जा रहा हूं वह देश का एक महत्वपूर्ण विषय है । हम हिन्दुस्तान में बराबर यह देख रहे हैं कि वर्षों से और सदियों से यह कृषि-प्रधान देश रहा है । हमारी 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है और गांवों का मूल आधार कृषि है । यदि हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रही और यदि हमने देश के किसानों और उनकी कृषि की तरक्की नहीं की तो निश्चित रूप से मानिये उसका असर हमारी राजनैतिक और आर्थिक स्थिति पर पड़े बिना नहीं रहेगा । और यही कारण है कि पिछले कई वर्षों में हम खाद्यान्न की दृष्टि से दूसरे देशों पर निर्भर रहे हैं । आजादी के बाद यह आवश्यकता थी कि हम अपने देश को परावलम्बी न होने देते और खाद्यान्न के उत्पादन में इतनी तेजी से प्रगति करते कि हमें दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं होना पड़ता । लेकिन चूंकि इस पुरातन देश में कृषि के आधुनिक औजार, कृषि का वैज्ञानिकरण और खेती के बारे में जो नये-नये प्रयोग होने चाहिए थे वह हम नहीं कर सके और किसानों को जो उसके लिए प्रशिक्षण मिलना चाहिए, उसके लिए जो साधन सुविधायें मिलनी चाहिए उसका उपयोग हम नहीं कर सके परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के अन्दर न हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सके, न हम अपने देश की आर्थिक नीति और आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके और न अपनी सामाजिक व राजनैतिक स्थिति को मजबूत बना सके । मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि आज अगर हम अपने देश के अन्दर यह चाहते हैं कि खाद्यान्न की दृष्टि से हम किसी पर निर्भर न रहें और हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर रहने वाले करोड़ों-करोड़ों किसान भाई, और गांवों में रहने वाले लाखों परिवार उन्नत हों, उन्हें हम उन्नत देखना चाहते हैं तो हमें उर्वरकों निर्माण के बारे में, उसके उपयोग के बारे में और उस के विकास के बारे में बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा । श्रीमन्, आंकड़े बताते हैं कि उर्वरकों का निर्माण हमारे यहां हो रहा है । एक फर्टिलाइजर कारपोरेशन है जिसके अन्तर्गत कई कारखाने चल रहे हैं और इसके अलावा गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कई कारखानों के द्वारा हमने खाद का निर्माण किया है । लेकिन जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी आदत पड़ गई है कि हम किसी क्षेत्र में जब कभी लहर आती है तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हम उसके लिए फीडिंग ऐटमास्फेयर तैयार नहीं करते । हमने कहा कि हमें इंजीनियर चाहिए देश के लिए, हमें टेकनीकल आदमी चाहिए, हमें डाक्टर चाहिए और हमारे देश ने इंजीनियर तैयार किए, डाक्टर तैयार किये लेकिन हम उन्हें काम नहीं दे सके । ठीक इसी तरह से जब यह वातावरण पैदा हुआ कि हम अपने देश किसानों को अधिक

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

से अधिक खाद दे सकें, देश के किसानों को हमने यह कहा कि हम तुम्हें अधिक खाद देंगे, उर्वरक देंगे, तुम अपनी खेती को सुधारो तो हम उनको उर्वरक नहीं दे सके । उसके साथ साथ खाद का इस्तेमाल कैसे किया जाय खाद का उपयोग करके कैसे साधन सुविधा के साथ अपनी खेती को वह उन्नत कर सके उसके लिए उनको कर्ज की सुविधा समय पर हमने नहीं दी उनको ऋण समय पर नहीं दिया और यही कारण है कि किसान अपनी खेती का सुधार नहीं कर सका । आज हमारे देश की स्थिति ऐसी है कि कुछ इलाकों के अन्दर जहां एक एकड़ में दो हजार मन गन्ना पैदा होता है, वहां उत्तर प्रदेश और बिहार के अन्दर केवल 500 मन गन्ना पैदा होता है । आज मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि केवल नारों के द्वारा हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर सकते । खेती के अन्दर जब तक हम प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के बारे में ध्यान नहीं देंगे तब तक अपने देश को हम आत्म-निर्भर नहीं बना सकते । यदि गांवों की जनता उन्नत होती है तो उनका धन देश के विकास के काम आयेगा । खेती में जो वह सोना उपजायेंगे उससे देश की तरक्की होगी । लेकिन वह उपजाएंगे कब ? जब हम उन को ट्रेन्ड करेंगे शिक्षित करेंगे ।

इसी भूमिका में जो देश के अन्दर आज उर्वरक कारखानों का निर्माण किया जा रहा है उसके ऊपर दो बातें मैं कहना चाहता हूं । यही मेरा मूल विषय है । देश में सरकारी क्षेत्र के अन्दर कई उर्वरक कारखाने काम कर रहे हैं । उनकी मार्केटिंग उनकी परचेजिंग और उनकी व्यवस्था के बारे में कई तरह की बातें कही जाती हैं । मैं इस पर अधिक नहीं कहना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमने प्रचार अधिक किया है, काम कम किया है । हमारे अधिकारियों ने श्रम किया है । ईमानदारी भी रखी है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां जिस तरह किसानों को समय पर खाद मिलनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए उसके लिए उनको आवश्यक निर्देशन मिलना चाहिए उसका इंतजाम अभी नहीं किया गया है । जो टार्गेट, जो आंकड़े हमने तय किये है उनको केवल हमने प्रचारित किया है । उन आंकड़ों के आधार पर अभी हमने उत्पादन नहीं किया है । एक ऐसी सर्वे भी हुई है जिसमें बताया गया है कि खाद तो तैयार है लेकिन लेने वाले नहीं हैं । मैं इसका दोष भी उन्हीं को देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए हमारे किसानों को तैयार नहीं किया, हमारी कृषि योजना का विस्तार इस ढंग से नहीं किया कि किसानों के अन्दर एक उत्साह पैदा हो एक उमंग पैदा हो । हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे पंजाब में, राजस्थान के गंगानगर इलाके में और महाराष्ट्र में किसानों में उत्साह पैदा हुआ है । लेकिन जहां उत्साह पैदा हुआ है वहां हमने खाद के दाम बढ़ा दिये है, फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ा दी है । और हमने कीमत बढ़ाकर के एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है कि साधारण किसान जिसके पास एक-एक दो-दो बीघा जमीन है वह इतनी महंगी खाद खरीद नहीं सकता और खेती में उसका प्रयोग करने के लिए इतनी साधन सुविधायें उसके पास नहीं हैं ।

आज हमारे देश में खाद निर्माण के कारखाने कई चल रहे हैं, कई निर्माणाधीन है, कम से कम 13 कारखाने चल रहे हैं और 8 कारखानों की परियोजना अभी निर्माणाधीन है, वह अंडर कांस्ट्रक्शन चल रहे हैं । उसके साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी सात कारखानों को और स्वीकृति दी है । और कई योजनाएं सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में स्वीकृत की हैं । अभी-अभी गोआ में आपने खाद का कारखाना स्वीकृत किया है । मीठापुर में भी एक प्लान है 50 करोड़ का । लेकिन इन

तमाम कारखानों का उत्पादन कब आयेगा इसके बारे में कोई भी तथ्य दृढ़ता से सामने नहीं आता है क्योंकि हमने सबसे ज्यादा अपने आप को निर्भर कर लिया है विदेशी पूंजी के सहयोग पर और विदेशी सहायता के ऊपर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम इस देश की आर्थिक नीति का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं तो हम यह काम विदेशी पूंजी के आधार पर और विदेशों के सहारे नहीं कर सकते। आज हमारे देश में इतनी सुविधायें हैं कि यदि हमने एक-एक चीज को निष्ठापूर्वक करने की कोशिश की होती और थोड़ा काम भी हाथ में लिया होता तो हम उसको पूरा कर पाते। श्रीमन्, हम बरौनी में खाद का एक कारखाना खड़ा कर रहे हैं। बरौनी के अन्दर एक ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, वहां हमने कोसी नदी पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया लेकिन खाद के कारखाने का निर्माण अभी तक कम्प्लीट नहीं कर पाए। ऐसी ही कई जगहें हैं जहां अगर हमारे अधिकारियों में निष्ठा होती, और एक प्रेरणा तथा मिशनरी भाव से उन्होंने काम किया होता तो देश के अन्दर जो चीजे 73-74 और 75 में पूरी होने वाली हैं वह जल्दी पूरी होतीं।

अब मैं अपने मूल विषय पर पुनः आता हूं। हमने कारखानों का निर्माण करने के बारे में पहल की है। मैं इस विषय में कतई कोई असंतुष्ट नहीं हूं। खाद के कारखाने सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भी लगाए गये हैं लेकिन किसान को खाद चाहिये और जल्दी चाहिए। इसलिए आप उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें। इसीलिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय असंतुलन नहीं हो। सभी प्रान्तों में हमको इस तरह के कारखानों का विकास करना चाहिए। मैं जानता हूं कि हमारे देश के अन्दर इस तरह की स्थिति नहीं है, कुछ इलाके पिछड़े हुए भी हैं, इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान का नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी-अभी राजस्थान में उदयपुर के निकट राक-फास्फेट का 100 मिलियन टन का एक बहुत बड़ा भण्डार मिला है। उस 100 मिलियन टन का भण्डार मिलने से इस देश की विदेशी मुद्रा की बहुत बड़ी बचत हुई है। हिन्दुस्तान में जितने फर्टिलाइजर कारखाने हैं, उनको कच्चे माल के रूप में राक-फास्फेट की जरूरत पड़ती है। खाद के कारखाने में उत्पादन की 80 परसेन्ट कास्ट सलफ्यूरिक एसिड और राक-फास्फेट की होती है। उदयपुर के पास राकफास्फेट का इतना बड़ा भण्डार मिलने से देश में एक नई आशा का संचार हुआ है, देश को ताकत मिली है कि हम अपने देश की सम्पत्ति का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे। लेकिन उस राकफास्फेट का क्या उपयोग हो रहा है? अगर हमें उसका उपयोग अच्छी तरह से करना है तो हमें वहीं उदयपुर के पास, जहां उसका भण्डार और कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में है, पाइराइट भी वहां मिला है, जो खाद के निर्माण के लिए आवश्यक है, उदयपुर के पास जयसमुद्र या उदयसागर के पास पब्लिक सैक्टर में खाद का कारखाना लगाना चाहिए। आज हमने देश के विभिन्न भागों में पब्लिक सैक्टर के अन्दर बड़े-बड़े फर्टिलाइजर प्लांट दिये हैं, लेकिन राजस्थान, जिसके पास कच्चा माल है, कोई कारखाना नहीं दिया है। अगर यह कच्चा माल दूसरी जगह जायेगा तो उसके उत्पादन का खर्च ज्यादा पड़ेगा, इस लिए मैं चाहता हूँ एक खाद कारखाना, जो राक-फास्फेट और पाइराइट पर आधारित हो, राजस्थान में दिया जाय। इस समय राजस्थान में पब्लिक सैक्टर में एक भी खाद का कारखाना नहीं है। गंगानगर जो राजस्थान नहर के बनने से हरा इलाका बनने जा रहा है, वहां की जमीन उपजाऊ हो जायेगी। कोटा के पास प्राइवेट सैक्टर में एक कारखाना है, जो यूरिया का उत्पादन करता है। मैं चाहता हूं कि

[श्री ओंकार लाल बोहरा]

उदयपुर राजस्थान में पब्लिक सैक्टर में खाद कारखाना लगाने के लिए केन्द्र सरकार शीघ्र निर्णय ले। राजस्थान सरकार ने भी आपसे ऐसी मांग की है। मैं बड़े पुरजोर शब्दों में अपने मंत्री डा० त्रिगुण सेन साहब और चव्हाण साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि उदयपुर में सार्वजनिक क्षेत्र में राकफास्फेट पर आधारित एक कारखाना लगाने के बारे में निर्णय करें, कम से कम उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए पहल करें, ताकि रिपोर्ट आने के बाद दो-तीन साल में वह अमली रूप ले सके।

एक और निवेदन भी मैं आपसे करना चाहता हूँ—आज देश के अन्दर जो इसकी मार्केटिंग व्यवस्था है, उसको ठीक किया जाना चाहिए। 50 किलो के बोरे में किसान को केवल 40 या 45 किलो माल ही मिलता है। मैं चाहता हूं कि आप बोरे के बजाय किसी और चीज का उपयोग करें, जिससे कि किसान को पूरा वजन मिल सके, 50 किलो के बजाय पौने-पचास किलो माल उसको न मिले।

आज भी हम को लाखों टन खाद का आयात करना पड़ता है। यदि इस आयात से बचना है तो हमें जो हमारे मौजूदा कारखाने हैं, उनके उत्पादन को तेजी से बढ़ाना होगा, उन कारखानों का विस्तार करना होगा।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जितनी भी स्वीकृत योजनायें हैं वे सिर्फ कागजी ही न रह जाय, कल्पना में ही न रह जाय उन में प्रगति होनी चाहिए। कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि हमारी इन योजनाओं में पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है। खेतड़ी की कौपर योजना को ही ले लीजिये। इनके भरोसे हम आगे की अन्य योजनाओं को तैयार नहीं कर सकेंगे और इस तरह से हमारे किसानों के अन्दर असन्तोष बढ़ेगा। आज वे जमीन के लिए लड़ रहे हैं, लैण्डलैस लोग जमीन मांग रहे हैं, वे खाद चाहते हैं, यदि ठीक टाइम पर उनके लिए खाद उपलब्ध कर दी जाय तो इससे देश की पैदावार बढ़ेगी, अन्यथा एक नई क्रांति का जन्म होगा जिसका सामना केन्द्र या किसी भी राज्य सरकार के लिए करना मुश्किल हो जायेगा। इन कारखानों को आप देश में कहीं भी खोलें, सभी हमारे कारखाने हैं, लेकिन राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में राकफास्फेट और पाइराइट पर आधारित कारखाना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर कच्चे माल का इतना बड़ा भंडार उपलब्ध है, जिससे 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वहां पर इस कारखाने को खोलने की घोषणा करें और उसके लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का शीघ्र प्रयत्न करें।

श्री शिवचन्द झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह बहस पिछले सत्र से चली आ रही है। उस समय जो पार्टिसिपेंट मेम्बर थे उनका बैलेटिंग हुआ था। बीच में एक सिलसिला यह चलाया गया कि पिछले सैशन से जो विषय आयेगा, उसके पिछले बैलेटिंग के अनुसार जो पार्टिसिपेन्ट मेम्बर होंगे, वही नाम रहेंगे। लेकिन मैं देखता हूं कि अब एक नई परिपाटी चालू हो गई है। सोमवार को जो विषय आया था, उसके लिए भी वही हुआ और आज भी वही हुआ, पुराने मेम्बरों के नाम बदल गये और फिर से बैलेटिंग किया गया। इस सम्बन्ध में एक कांस्टेंट नीति चलानी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि जो बैलेटिंग पहले हुआ था, उसको अब कैसे बदल दिया गया?

सभापति महोदय : मैं लिस्ट को देख कर जवाब दूंगा, तब तक प्रश्न पूछने दीजिये।

श्री बेनी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, हमारे देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे मंत्रालयों के विभिन्न डिपार्टमेंट्स में

अपने-अपने कानून अलग से चलते हैं। उर्वरक का सम्बन्ध पानी से बहुत ज्यादा है। आप केवल उर्वरक दे दें और पानी न दें तो उस से कोई फायदा नहीं होगा। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि जहां पानी नहरों से ज्यादा मिलता है, वहां उर्वरक पहुंचाये जाने चाहिये, लेकिन जहां पानी नहीं है वहां उर्वरक देने से कोई फायदा नहीं होता है। इस पृष्ठभूमि में मैं दो-तीन प्रश्न पूछना चाहता हूँ—

पहला— 1 अप्रैल, 1969 को हमारे यहां 200 करोड़ रुपये का उर्वरक का स्टाक था, मैं जानना चाहता हूं कि उस का उपयोग किस तरह से किया गया ?

दूसरा— 1969-70 के एकाउन्ट में फर्टिलाइजर कारपोरेशन को 4 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। हमारे किसान गरीब हैं, उन्हें सहायता की जरूरत है, मैं प्रार्थना करूंगा कि नो-प्राफिट-नो लौस के बेसिज पर फार्टिलाइजर का दाम कम से कम निश्चित करें जिससे किसानों को कम कीमत पर मिल सके।

तीसरा— अभी हमारे देश के अन्दर फर्टिलाइजर का उत्पादन बढ़ने की बहुत आवश्यकता है। इस के लिये अभी गोवा में बिरलाओं को, मीठापुर में टाटा को लाइसेंस दिये गये हैं। हम मिक्स्ड इकानमी के हिमायती हैं। हम चाहते हैं कि सरकारी उद्योगों के साथ-साथ प्राइवेट सैक्टर भी उन का मुकाबला करें, हमें मालूम होना चाहिये कि किस तरह से सरकारी क्षेत्र में काम होता है और किस तरह से प्राइवेट क्षेत्र में काम होता है। इस लिये में जानना चाहता हूं कि गोवा और मीठा पुर में जो कारखाने बनने वाले हैं उन में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायगा।

माइन्ज एण्ड मैटल्ज का महकमा पहले भी सेन साहब के अधीन था और अभी भी उनके अधीन है। अब श्री नीतिराज सिंह उस के इन्चार्ज हैं। हमारे खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में सल्फ्यूरिक एसिड बाई-प्रोडक्ट के रूप में हम को मिलने वाला है, जिसकी हमें कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। सलफ्यूरिक एसिड से खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट में पब्लिक सैक्टर में भी एक खाद का कारखाना बनने वाला है—मैं जानना चाहता हूँ कि वह कब तक बनेगा, उस में देर क्यों हो रही है ?

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूँ— हमारी जो चलती-फिरती फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, जो हमारा पशुधन है, गाय भैंसें हैं— क्या मंत्री महोदय ने कोई ऐसा हिसाब लगाया है कि जितना रुपया हमारा इन फर्टिलाइजर कारखानों में लगा है, यदि उतना रुपया हम गाय-भैंसों के पालने पर लगावें तो उस से दूध के अलावा फर्टिलाइजर भी मिलेगा। क्या आपने इस का कोई आर्थिक विश्लेषण किया है। इस लिये मैं जानना चाहता हूँ कि इस चलती फिरती फर्टिलाइजर फैक्टरी, हमारे पशु धन के विकास के लिये आप क्या चेष्टा करने जा रहे हैं ?

SHKI S. KUNDU (Balasore) : Recently the Government announced that they were going to put up a fertiliser plant at Paradip. Some months before that they announced that they would put up a coal-based fertiliser plant at Talcher. I must thank both Dr. Triguna Sen and Mr. D. R. Chavan who have taken keen interest in seeing that the backward States get these plants. But I am sorry to state that no positive work has started in any of these places. On Paradip they are supposed to begin with the feasibility report. But nothing has been reported. In Talcher also no work has been started. I am told they are held up because of some trouble about foreign exchange I hope they would not try to sabotage these plants on this score. It would be better if the Minister would make a statement of the energetic steps they are taking to see that the construction work of these plants start within a very short period.

Secondly, about the cost of fertilizer the Estimates Committee has already reported that the margin between the ex-factory price and the price at which

[Shri S. Kundu]

it is sold to peasants is very high and yet so far government have not done anything to reduce it and bring it to a reasonable level. A major portion of this goes to the distributing agencies of the monopolists. Unless this is changed the farmers would not find it economic to use fertilizers.

Thirdly, the utilisation of fertilizer per capita per are has gone down during the last two years as compared to previous years. If that is true, it is very alarming because in that case in the long run the food production will go down, because the affluent and rich peasants are producing only up to a certain level and not beyond that. So, unless the smaller and marginal level peasants are encouraged to use more and more of fertilizer the *per capita* consumption of fertilizer would go down and consequently food production also I want categorical answers from the Minister to these points.

श्री शिव चन्द झा : सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि बिड़ला को जो गोवा में फर्टिलाइजर प्लान्ट का लाइसेन्स दिया गया है, जब उसकी जांच के लिए इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है और दूसरी बातें चल रही हैं तो फिर किन वजूहात से आपने बिड़ला को वह लाइसेन्स दिया ? क्या आपका यह काम मानोपलीज् एण्ड रैस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज् ऐक्ट के खिलाफ नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि जो आपकी नीति है वह यह कि नाफ्था बेस्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट लगाये जायं लेकिन आपने टाटा को मीठापुर में अमोनिया बेस्ड फार्टिलाइजर प्लान्ट लगाने की इजाजत दी जिसमें कि ज्यादा फारेन एक्सचेंज खर्च न ना पड़ेगा तो क्या आप अपनी नीति के खिलाफ यह काम नहीं कर रहे हैं ? क्या आपका यह काम भी मानोपलोंज् एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज् ऐक्ट के खिलाफ नहीं है ? और क्या आपने इस सिलसिले में बिड़ला और टाटा के मुताल्लिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कौंसिल से क्लियरेन्स ली थी ? आखिरी बात यह है कि मेरे पास इस बात के बहुत से इंस्टासेज हैं कि आप बहुत इनएफेक्टिव रहे हैं और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के पास ब्यूरोक्रेटिक पावर्स हैं तो मैं जानना चाहता हूं क्या आप दोनों मिनिस्टर्स भी मीनिंगफुल होंगे, अगर उसमें कहीं पर घांधली पायेंगे तो उनको हटाकर मीनिंगफुल बनेंगे ? मेरे पास इंस्टासेज् हैं, मैं जानना हूं कि आप दोनों इनएफेक्टिव रहे हैं इसलिए क्या आप कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें कि फर्टिलाइजर के मामले में आप जो नीति चलाना चाहते हैं उसमें पूरी तरह से सफल हों ? यही दो तीन बातें मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN) : Mr. Chairman, I listened to the speech of my hon. friend, Shri Onkar Lal Bohra, and the questions raised by the hon. Members with rapt attention. I will not take much time of the House and I shall be as relevant as I could be.

The first point that has been raised by my hon. friend is that India is an agricultural country. Yes, it is an agricultural country. There are about 5,50,000 villages where about 80 per cent of the people stay. If India is to grow big, its villages must prosper. To bring about prosperity in the villages the means of production, that is, agriculture must prosper.

He also made a reference to the scientific developments that have taken place and how the scientific development should be harnessed so far as agricultural production is concerned. In that connection he made a reference to fertiliser production in the country as to what are the targets, what is going to be the production and what is being planned by the Government for the future.

It is true that since independence we have not been able to build up fertiliser plants in the country so as to produce enough of fertilisers, which fertilisers should go into agriculture and bring about agricultural prosperity. As a matter of fact, our consumption and production targets were not fulfilled. Therefore we had to depend much more on imports of foodgrains.

The import of foodgrains during all these years has drained the resources of the country to a considerable extent. I understand that about Rs. 2,600 crores have been spent on the import of foodgrains and nearly Rs. 722 crores have been spent on the import of fertilisers from 1950-51 to 1968-69. Therefore, this big drain, that is, the import bill that has got to be paid for importing fertilisers and foodgrains because fertilisers were not produced and applied, has got to be stopped. Therefore, the target of capacity fixed for the Fourth Five-Year-Plan is 3.7 million tonnes.

What is the present position ? The present position is that some of the plants which are in production have got a capacity of 1.34 million tonnes. My hon. friend referred to some of the projects which are under construction; for example, Namrup expansion, Durgapur, Barauni, Cochin and Madras fertiliser projects. Some of these projects which are under implementation will add nearly 1.2 million tonnes to the capacity which is already in production. Therefore by about 1971-72, when these fertiliser projects which are under implementation and construction are completed and all these projects go on stream, the total capacity would be 2.54 million tonnes and the gap so far as the production of nitrogenous fertilisers is concerned will be about 1.2 million tonnes.

With regard to the position about phosphatic fertilisers, R_2O_5, the plants which are in production have a capacity of .421 million tonnes and the plants under implementation would have a capacity of .423 million tonnes. The total capacity, therefore, would be .844 million tonnes as against the target of 1. million tonnes fixed for the Fourth Five-Year Plan. So, there will be a gap there also.

My hon. friend made a reference to the coal-based plants. Instead of answering a specific question I am answering in a general way. The Government has got in view the establishment of some fertiliser projects in the country. There are going to be three coal-based projects at Talcher, Ramagudem and Korba. The Trombay expansion is also contemplated which is likely to be based on imported ammonia. Nangal expansion is also contemplated which is going to be based on low sulphur heavy stock and Cochin phase II also will be expanded based on imported ammonia.

18.00 hrs.

The Haldia Fertiliser project is under contemplation. The techno-economic feasibility report has been prepared which is under consideration. What is going to be the capital cost of all these projects ? It is going to be about Rs. 399.36 crores and the foreign exchange component will be of the order of about Rs 111 crores. It is not that the Government is not doing anything. The Government is very serious to see that fertiliser production in the country increases so that there is no shortage felt and the farmers of the country get fertiliser at a cheaper rate. You cannot get fertiliser at a cheaper rate unless all the plants which are under production run to the rated capacity. You have also to put in more and more plants in the country so that the fertiliser production increases to meet the demand of the people in the country. There should not be any gap. But even in spite of all these plants running to the rated capacity and some of the plants which are under consideration of the Government and in private sector coming up, there will still be a gap between demand and supply of the order of about 6.2 million tonnes, both phosphatic and nitrogenous, which will require upto the end of the Fourth Plan a very huge sum of money for importing them. This is the position. Therefore, the Government is very serious about all these things.

Then, my hon. friend, Shri Kundu said about the Talchar plant. So far as the foreign exchange part is concerned, I may inform him that is all cleared. I am quite confident that the plant at Talcher based on coal is likely to be completed in a period of 3 to 4 years. Normally, it takes about 4 to 5 years to complete the construction.

SHRI S KUNDU : But you have not yet started any construction,

SHRI D. R. CHAVAN : My hon. friend will remember that my senior collague Dr. Triguna Sen went and had the foundation stone laying ceremony there. The foreign exchange part and everything has been cleard. There will not be any trouble. I may mention for his information that this plant is going to be a very capital-intensive plant costing about Rs. 70 crores of which about Rs. 20 crores will be in foreign exchange. As I said, the foreign exchange

[Shri D. R. Chavan]

part has been cleared. So far as this fertiliser plant is concerned, there will not be any difficulty. I am quite confident that that will be completed within a period about 4 years.

As regards the Paradip plant, I may mention the position about it. Recently, the Government has agreed on the preparation of a feasibity report for the establishment of the fertiliser plant at Paradip. The F.C I. is being asked to prepare a techno-economic feasibility report based on imported ammonia. So far as the import of ammonia is concerned, the policy of the Government is that ammonia that will be imported will be used only in the public sector projects. Previously, there was a proposal by a private party for establishing a fertiliser plant at Paradip. But since this decision has been taken that it will be based on imported ammonia, it will be in the public sector. The F. C I. has been asked to prepare a techno-economic feasibility report. So, Orissa is likely to get two plants one costing about Rs. 70 crores and another costing about Rs. 30 to 40 crores.

Then, my hon. friend there said that fertiliser should be available at a cheaper rate and that there should be proper marketing organisation and all that. That will necessarily have to be built because the public sector projects have to compete with the private sector projects. There will be a fierce competition. Unless the public sector projects take steps from now on to organise marketing, etc., they cannot compete with the private sector projects. Those steps are being taken by the F.C.I. and other public undertakings. I am quite confident that when the fertiliser production increases, the fertilisers will be available to the farmers at a cheaper rate.

My hon. friend who raised this discussion on two points, that is, the time taken for establishing fertiliser plants and the availability of foreign exchange. These were the two points which he wanted to raise.

But, Sir, he did not touch this points. He want off at tangent. But I understood the point which he wanted to raise, that is the fertiliser complex to be established in Rajasthan based on the pyrites deposits and the rock phosphate deposits which have been found. Recently I got an opportunity of going and paying a visit to the Jamarkotda deposit. It is a good deposit, which has been found. Till now we have been importing rock phosphates from foreign countries. Now I have to explain his point because he has raised the discussion on it specifically.

What is the present position ? What has been done before this and what is the present position ? These pyrite deposits have been located in Rajasthan in Saladipur area The deposits are of the order of 115 million tonnes. Rock phosphates have also been located in Udaipur and Birmania in Jaisalmer districts. Udaipur I have seen recently. The indicated deposits are of the order of 59 million tonnes. When I went there, the Geological Officer there said that they are exploring He said he was trying to assess the ultimate reserves and he said that the reserves are going to be very big. It should be nearly 100 million tonnes. With a view to developing these deposits, it was decided that the Pyrites and Chemicals Development Co which is already exploiting the Pyrites deposits, in Amjhore area of Bihar should undertake the exploitation of these deposits. The name of the company was accordingly changed and it was called Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. When the Company applied to the Government of Rajasthan for the grant of mineral rights, the Rajasthan Government insisted, as a condition precedent to the grant of such rights, *i.e.* the mineral rights, that a fertiliser factory based on these deposits should be set up in Rajasthan. That was the State Governments demand when the Company went for demanding mineral rights. They said "We are prepared to grant the mineral rights but on the condition that after the deposits are exploited, the fertiliser plant will be established in Rajasthan." Therefore, it was decided to set up a Working Group in the Ministry of Petroleum and Chemicals to consider the technical and economic feasibility of setting up a fertiliser plant based on pyrites and rock phosphates in Rajasthan. The Working Group which was set up on 17th August 1968 consisted of experts like the Chief Project Officer of the Ministry of Petroleum and some reprentatives of some other departments and they submitted their report sometime in the year 1969. Now this is very important. The Working Group

has come to the conclusion—I am putting it in inverted commas :

"Based on the total resources indicated as well as inferred and taking into account the fertiliser programme especially in relation to the phosphate there seems to be a *prima facie* case for the establishment of a fertiliser complex at Saladipura or Udaipur."

They have further recommended :

"Considering the estimated requirements of P_2O_5 by 1973 74 in the economic marketing zone and the likely availability of P_2O_5 in the zone a capacity of 2,00,000 tonnes of P_2O_5 per year can be considered in a fertiliser complex in Rajasthan. It takes a total period of..."

SHRI ONKAR LAL BOHRA : Saladipura has got only Pyrites.

SHRI D. R. CHAVAN : Where the plant is to be located you leave it to the technical experts. It will take a total period of 4½ to 5 years to commercially mine and utilise the raw materials.

Now, what further steps were taken ? My senior colleague, Dr. Sen called a meeting where the representative of the Rajasthan Government was also invited and the Industry Minister of Rajasthan came and attended that meeting. In that meeting it was decided that Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd. should be entrusted with the task of exploratory-*cum*-mining production and coordinate the activities of beneficatian etc. It was noted, as a result of discussions, that a period of 2 years may be taken for completing the investigations for the exploratory-*cum*-production mining and the benefication of pyrites and rock phosphate and another 3 years for the establishment of a fertilizer complex for which a feasibility report would be prepared by the F. C. I.

In the Department of Mines and Metals, a Standing Committee was set up to keep a close watch on the progress of action taken in this regard. The Standing Committee has so far held two meetings.

What is the present position ? The present position is this. The P. P. C. Limited have started work at Saladipura Pyrite deposit. The Company have prepared an exploitation-cum-production report. The Company have also taken up the benefication tests.

As regards rock phosphate, the Government of Rajasthan have already commenced mining in the Jhamarkotra area. At the end of 1969 70, the total production was 96,898 tonnes.

At the second meeting of the Standing Committee, it was indicated that it will be better that the P. P. C. first indicated the best ore that they could supply and its cost and based on that the F. C. I. could attempt a suitable design for the Fertilizer Complex. This is the present position.

I am quite confident that my hon. friend who raised the discussion will be satisfied with what I have said.

Now that my hon. friend has raised a question about Goa, I would say, at the time the Demands for Grants of this Ministry came up, the matters about Goa Fertiliser were very thoroughly discussed. The letter of intent was granted sometime in 1964 and it was converted into industrial licence in 1966. What was done by the end of December, 1969 was that the green signal was given to the sponsors or the promotors of this plant to start with the construction work, because they submitted a financing plant to the satisfaction of the Government. That is the position in this case.

Now, as far as the Mithapur Project is concerned, it has been approved in principle, but the project would be cleared, subject to the clearance given by the Monopolies Commission, that is, under the Monopolies and the Restrictive Trade Practices Act. That is the position in in this regard.

श्री शिव चंद्र झा : बिड़ला के खिलाफ इनक्वायरी चल रही है। फिर भी गोआ में फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगाने का उनको लाइसेंस कैसे दे दिया गया ?

SHRI D. R. CHAVAN : The requirement of fertiliser is so great in the country that I would request my hon. friend not to bring in different types of arguments ; let us have fertiliser plants throughout the country. If the Birlas in any place indulge in some hanky-panky business, the arms of law and

[Shri D. R. Chavan]

Government are big enough. You can take over if you like, if the consensus of the House is like that. The industry must grow. In the context of the fertiliser demand during the next 3 or 4 years, about Rs 700 to Rs. 800 crores would be required for import of fertilizers. That means a big drain for the country and that is why we have to take all these steps.

So, I hope my hon. friend will be satisfied with what I have said. I am grateful to all tne hon. Members who have participated in the discussion.

18.15 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 3, 1970/Sravana 12, 1892 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.